Research Paper | Political Science | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 9 | Issue : 6 | June 2023



वैश्विकरण के दौर में जी–20 की भूमिका : एक अध्ययन

डॉ संजय कुमार झा

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा, ल0 ना0 मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा

INTRODUCTION

लगभग 14 वर्ष पहले ग्लोबल इकोनमी को एक बड़ा झटका लगा था, जब एशियाई वित्तीय संकट ने आर्थिक संवृद्धि की दर को बहुत धीमा कर दिया था और एक बार फिर से 2020 से विश्व अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है और कई बड़े देश भी आर्थिक सुधार करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। इन दोनों ही दौर के आर्थिक संकटों की एक बात जो गौर करने वाली है, वह है जी–20 संगठन की भूमिका।

एशियाई वित्तीय संकट के प्रभावों को देखते हुए ही 1999 में जी–20 का गठन हुआ और अब फिर से जब दुनिया आर्थिक, भू–राजनीतिक समस्याओं से घिरी है तो उसका समाधान तलाशने के लिए जी–20 का सम्मेलन हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। इस सम्मेलन की एक खास बात, जिस पर ध्यान जाना चाहिए वह, यह है कि अब जी–20 के विकसित देशों ने ग्लोबल इकोनमी की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे इमर्जिंग मार्केट इकोनमी की भूमिका और क्षमता को मान्यता देना शुरू कर दिया है।

इसका प्रमाण यह है कि वर्ष 2023 में जी–20 का आयोजन भारत कर रहा है तो वहीं 2024 और 2025 में इसका आयोजन क्रमशः ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका करेंगे। बाली में जारी किए गए जी–20 के उद्घोषणा से पता चलता है कि विकसित और विकासशील देश जी–20 को ग्लोबल इकोनमिक रिकवरी का सबसे प्रभावी जरिया मान रहे हैं। शायद इसलिए राष्ट्रों के बीच अपने आर्थिक मतभेदों और महत्वाकांक्षाओं को परे रखकर, आर्थिक संरक्षणवादी नीतियों को छोड़कर वैश्विक आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने पर सहमति दिखाई दे रही है।

रूस–यूक्रेन युद्ध और अन्य भू–राजनीतिक तनावों ने यूरोपीय देशों खासकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसलिए जी–20 के बाली समिट में राष्ट्रों ने कहा कि वे रूस की युद्ध की बर्बर और पाश्विक मानसिकता का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि रूस बिना किसी शर्त के यूक्रेन के विरुद्ध अपनी सैन्य कार्यवाही को बंद करे, क्योंकि युद्ध अब बहुत बड़ी मानव त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है और रूल बेस्ड इंटरनेशनल आर्डर और लोकतांत्रिक मूल्य इस बात की इजाजत नहीं देते कि कोई देश अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए वैश्विक शांति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की आहुति देने पर तुल जाए।

बाली में आयोजित जी–20 बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी कहा कि किसी भी हालात में परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए। दोनों देशों ने यह भी कहा है कि परमाणु हथियार से कभी भी युद्ध नहीं जीता जा सकता है। रूस की ओर से यूक्रेन को दी जा रही परमाणु धमकियों की भी दोनों देशों ने निंदा की है। चीन का ऐसा दृष्टिकोण पश्चिमी देशों को एक अलग ही प्रकार का साहस दे रहा है, क्योंकि चीन बहुत कम अवसरों पर स्पष्टवादी हो पाता है।

जी–20 नहीं चाहता कि विश्व में क्रिटिकल सप्लाई चेन धराशायी हो जाए, जी–20 के सदस्य नहीं चाहते कि कोविड महामारी से त्रस्त रह चुके देश अब युद्धजनित ऊर्जा समस्या का सामना करें। जी–20 के देश चाहते हैं कि अब एक ऐसे धारणीय विकास के लिए काम किया जाए, ताकि आर्थिक मंदी की आशंकाओं को समाप्त किया जा सके। इस बात की प्रतिध्वनि इंडोनेशिया के जी–20 की अध्यक्षता के थीम "रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर" में सुनाई देती है। जी–20 के देशों ने सतत विकास लक्ष्यों की समय रहते प्राप्ति के लिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स से कहा है कि वे इस दिशा में वित्तीय सहयोग की मात्रा और गति दोनों को बढ़ाए, ताकि खाद्यान्न समस्या से निपटना राष्ट्रों के लिए आसान हो सके।

जी–20 देशों ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पांस ग्रुप ऑन फूड, एनर्जी और फाइनेंस को आज की स्थिति को देखते हुए और सक्रिय भूमिका निभाने का आवाहन किया है। जी–20 बाली समिट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देशों को कोविड महामारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सर्वाधिक सुभेद्य वर्गों (वल्नरेबल कम्युनिटी) की पहचान करनी होगी (जैसे महिला, बच्चे, सीमांत कृषक, मछुआरे आदि) ताकि इनके लिए सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा का प्रबंध किया जा सके।

दुनिया को आज 'वन हेल्थ एप्रोच' को क्रियान्वित करने के लिए काम करना चाहिए। 'वन हेल्थ' व्यक्तियों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को संतुलित एवं अनुकूलित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र शामिल हैं। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से भोजन एवं पानी की सुरक्षा, पोषण, जूनोटिक यानी पशुजन्य बीमारियों के नियंत्रण (रोग जो जानवरों और मनुष्यों के बीच फैल सकता है, जैसे फ्लू, रेबीज और रिफ्ट वैली बुखार), प्रदूषण प्रबंधन और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (उद्भव) के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।

जी –20 विश्व का एक अनौपचारिक व्यापारिक समूह है जिसका न तो स्थायी मुख्यालय है, न सचिवालय और न ही स्थायी स्टाफ। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों जैसे आर्थिक मंदी, निर्धनता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, खाद्य असुरक्षा, काला धन, आर्थिक अपराध आदि से निपटने के लिए रणनीतियां बनाता है। इसने अंतरराष्ट्रीय कर प्रशासन हेतु अपेक्षित सुधारों के लिए राष्ट्रों से समय–समय पर अपील की है। वैश्विक स्तर पर कंपनियों द्वारा कर की चोरी को रोकने और गंभीर आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए भी जी– 20 ने एजेंडा निर्धारित किया है।

भारत जी20 के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उभरा है – जो विश्व आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को नया आकार देने में योगदान देने और प्रभावित करने में सक्षम है। सितंबर 2016 में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का एक महत्वाकांक्षी बहुआयामी एजेंडा है, जैसे बुनियादी ढांचे के विकास, समावेशी विकास, ऊर्जा दक्षता के लिए वैश्विक अधिशेष को तैनात करने से लेकर आतंकवाद और काले धन को कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई तक। शिखर सम्मेलन में भारत का मुख्य एजेंडा रोजगार सृजन, स्थिर वित्तीय बाजारों और वैश्विक व्यापार व्यवस्थाओं के लिए स्थिर और टिकाऊ वैश्विक विकास पर केंद्रित होगा। जी20 शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा के अनुसार, देश व्यापार और निवेश के अलावा गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर जोर देगा।

हालाँकि व्यापार और निवेश हमेशा जी20 के एजेंडे में रहे हैं, चीन इन्हें उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए, यह जरूरी है कि भारत इन्हें गरीबी के मुद्दे से जोड़े। यह अमेरिका सहित विकसित देशों की मांग के अनुसार मध्यम अवधि में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग पर जोर देगा। काले धन पर रोक लगाने के लिए देशों के बीच सूचनाओं का स्वतः आदान–प्रदान भी इसके एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता वाला विषय है। हालाँकि इस मुद्दे पर जी20 देशों के बीच सहमति है, लेकिन शायद ही कोई ठोस प्रगति हुई है। आधार क्षरण और लाभ साझाकरण (बीईपीएस) का मुद्दा भी है, जो कर नियोजन रणनीतियों को संदर्भित करता है और जो कर नियमों में अंतराल और बेमेल का फायदा उठाकर कृत्रिम रूप से लाभ को कम या बिना कर वाले स्थानों पर स्थानांतरित करता है जहां बहुत कम या कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होती है। जिसके परिणामस्वरूप समग्र कॉर्पोरेट कर का भुगतान बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। बीईपीएस भारत जैसे देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी निर्भरता कॉर्पोरेट टैक्स, विशेषकर बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर है।

भारत ने जिस प्रकार कोविड संकट के दौरान सारे विश्व को कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवा कर मानवता की सेवा की, उसी प्रकार जी–20 के माध्यम से भारत आज विश्व के समक्ष आ रही चुनौतियों और समस्याओं के समाधान के लिये विश्व की आवाज बनेगा। समावेशी विकास, समावेशी वित्त और समानता आज की सबसे बड़ी आवश्यकताएँ हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण के लिये जीवन मूल्य का जो मंत्र दिया है, उसे जी–20 के माध्यम से विश्व के कोने–कोने में पहुँचाया जायेगा। विश्व की गरीब जनसंख्या को ध्यान में रखकर नवीकरण और नियोजन पर अधिक ध्यान दिया जाये। विश्व के लिये नया विकास एजेंडा भारत बनायेगा।

भारत में होने वाली जी–20 समिट के परिप्रेक्ष्य में विशेष थिंक–20 कार्यक्रम में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ''पर्यावरण सम्मत जीवन–शैली के समावेशी विकास'' विषय पर हुए प्लेनरी सेशन में वक्ताओं ने यह बात प्रमुखता से रखी। सत्र की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, साउथ अफ्रीका, प्रो. एलिजाबेथ सिडिरोपोलस ने की। समाहार वक्तव्य में उन्होंने कहा कि आज विश्व में वैश्विक वित्तीय संरचना, नवाचार और समावेशी विकास की आवश्यकता है। भारत की अध्यक्षता में हो रही जी–20 समिट इन उद्देश्यों को अवश्य पूरा करेगी।

प्रमुख वक्ता के रूप में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएसए के सेंटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के निदेशक प्रो. जैफ्रे डी सैश ऑनलाइन शामिल हुए। प्रो. सैश ने कहा कि आज विश्व के समक्ष आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिये वैश्विक वित्तीय संरचना की आवश्यकता है। इस कार्य में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स संस्था दिल्ली के प्रो. अशोक खोसला ने कहा कि जी–20 वह मंच है, जिसके माध्यम से हम आज विश्व के समक्ष आ रही समस्याओं यथा आतंकवाद, प्रदूषण, जीवन–पद्धति, जीवन–मूल्य, जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों का विलोपन, मंदी आदि का निराकरण कर सकते हैं। हमें दुनिया को ''इक्यूटेबल ग्रीन फ्यूचर'' देना होगा। पूरे विश्व और लोगों की समृद्धि हमारा लक्ष्य है। हमें सभी को स्थिर आजीविका देनी होगी और साथ ही पर्यावरण को पुनर्जीवित करना होगा। बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे उद्योगों के माध्यम से अधिक रोजगार सृजित करने होंगे।

बांग्लादेश से आये सीवीएफ संस्था के श्री अबुल कलाम आजाद ने वर्चुअल माध्यम से कहा कि आज विश्व को जलवायु समृद्धि योजना (क्लाइमेट प्रोसपेरिटी प्लान) अपनाना होगा। यह प्रकृति आधारित योजना है, जिसे बांग्लादेश ने अपनाया है। इसके माध्यम से प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों के लिये रोजगार के अवसर बनाये जाते हैं। यह योजना वन अर्थ – वन फैमिली – वन फ्यूचर की जी–20 की अवधारणा को पूरा करती है। सभी जी–20 देश अपने–अपने देश के लिये ''क्लाइमेट प्रोसपेरिटी'' प्लान बनायें।

येल यूनिवर्सिटी यूएसए के दर्शन शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर थॉमस पोगे ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के वैश्विक विजन, पर्यावरण के लिये भारतीय जीवन पद्धति, नवीकरण और नियोजन की परिकल्पना की सराहना की। उन्होंने ''इंटरनेशनल ग्रीन फण्ड'' बनाये जाने और समावेशी वित्त की आवश्यकता पर जोर दिया। पेरिस पीस फोरम के डायरेक्टर जनरल श्री जस्टिन वैसे ने फिस्कल बजट, वित्तीय संरचना और क्लाइमेट कंटेन्ट पर वर्चुअली प्रकाश डाला है।

भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के वरिष्ठ राजनैतिक सलाहकार डेविड व्हाइट ने भारत में जी–20 के मुद्दों पर शासकीय और अशासकीय, दोनों स्तरों पर सराहनीय कार्य के लिये भारत सरकार को बधाई दी। जेनेवा के प्रथम सचिव एकिनडेजी एडेनिपो ने कहा कि जी–20 मुद्दों के समाधान में विश्व भारत की आवाज बनेगा। विश्व में समावेशी विकास की कमी को दूर किया जाना आवश्यक है। इस कार्य में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने विश्व को कोविड वैक्सीन दिलवाने के लिये प्रधानमंत्री श्री मोदी की सराहना की।

जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रो. गुलशन सचदेवा ने कहा कि विश्व के लिये नया विकास एजेंडा भारत बनायेगा। भारत हमेशा विश्व की आवाज रहा है। वैश्विक वित्तीय सुधार, जलवायु परिवर्तन, भू–राजनैतिक अस्थिरता, मंदी सभी क्षेत्रों में जी–20 की भारत की अध्यक्षता महत्वपूर्ण होगी। भारत इसे राष्ट्रीय स्तर पर तो समावेशी बना ही रहा है, सभी के सहयोग से इसे वैश्विक स्तर पर भी समावेशी बनाया जायेगा। जी–20 की हालिया आयोजित बाली समिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है। यह मोदी की मजबूत विदेश नीति और दृष्टिकोण को दर्शाता है। कूटनीति और संवाद के माध्यम से इसे रोकने पर जोर दिया जा सकता है।

REFERENCES

1. https://www.jagran.com/politics/international-g-20-summit-2022-seeking-the-role-of-g-20-in-the-midst-of-global-crises-jagran-special-23213943.html
2. https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=20230116N357&fontname=Mangal&LocID=32&pubdate=01/16/2023
3. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/g20-august-2012.pdf
4. https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/G20_Brief_for_website_-_27.10__1___1_.pdf